पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आम आदमी के बीच जाकर उनके साथ समय बिताने लगे हैं। इस बात को लेकर इन दिनों वो रोज चर्चा में रहते हैं। राहुल गांधी शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को संबोधित करने जयपुर आये तब यहाँ भी उन्होंने एक ऐसा मौका ढूंढ ही लिया। राहुल गांधी ने महारानी कॉलेज जाकर वहां छात्राओं के साथ बातचीत की और फिर एक स्टूडैंट की स्कूटी पर पीछे बैठकर मानसरोवर (जयपुर) स्थित सभास्थल पर पहुँचे। राहुल को अपनी स्कूटी पर पीछे बैठाने वाली स्टूडैंट भी काफी उत्साहित नज़र आई।

खालिस्तानी आतंकी पन्नू और निज्झर की सभी सम्पत्ति एन.आई.ए ने जब्त की

जालंधर में आतंकी के घर के बाहर एन.आई.ए. ने नोटिस चिपका दिया है कि, अब यह सम्पत्ति केन्द्र सरकार की है

जालंधर , 23 सितंबर (वार्ता)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत चंडीगढ़ और अमृतसर में प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एस.एफ.जे.) संगठन के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

एन.आई.ए. मोहाली अदालत के आदेश पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्झर के घर पर भी कार्रवाई हुई है। जालंधर जिले के भारसिंहपुरा गांव में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्झर के घर के बाहर संपत्ति जब्ती का नोटिस चिपका दिया है।

चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में पन्नू के आवास के बाहर चिपकाए गए संपत्ति जब्ती नोटिस में लिखा है, मकान नंबर 2033 का 1/4 हिस्सा सेक्टर 15-सी, चंडीगढ़, गुरपतवंत सिंह पन्नू के स्वामित्व में, जो एन.आई.ए. मामले आर सी ए-19/2020/एन.आई.ए./डी.एल.आई . में 'घोषित अपराधी' है, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 33 (5) के तहत राज्य द्वारा जब्त कर लिया गया है।

- **गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका स्थित अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस (एफ.एस.जे.) के संस्थापकों में से एक हैं और अमेरिका, कैनडा और ब्रिटेन में सिखों के लिए एक अलग राज्य, जिसे वे खालिस्तान कहते हैं, की सक्रिय रूप से पैरवी करते हैं।**

इसी तरह का नोटिस अमृतसर में गुरपतवंत सिंह पन्नू के पैतृक गांव खानकोट में उनकी कृषि भूमि पर भी लगाया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2020 में दर्ज एक आतंकवादी मामले के संबंध में गांव में पन्नू की 46 कनाल कृषि भूमि जब्त कर ली है। पन्नू के पिता मोहिंदर सिंह पन्नू विभाजन से पहले तरनतारन के पट्टी उपमंडल के नाथू चक गांव के निवासी थे। विभाजन के बाद परिवार अमृतसर के खानकोट गांव में स्थानांतरित हो गया।

गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका स्थित अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस (एस.एफ.जे.) के संस्थापकों में से एक हैं और अमेरिका, कैनडा और ब्रिटेन में सिखों के लिए एक अलग राज्य, जिसे वे खालिस्तान कहते हैं, की सक्रिय रूप से पैरवी करते हैं। जुलाई 2020 में, पन्नू को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी नामित किया गया था और दो महीने बाद, सरकार ने कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 51 ए के तहत उसकी संपत्तियों की कुर्क का आदेश दिया।

पन्नू भारत के खिलाफ अभियान चला रहा है और अपने गृह राज्य पंजाब में सिख युवाओं को आतंकवाद में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। वह तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह के एक प्रमुख आयोजक रहे हैं, जिन्होंने दुनिया भर के सिखों को इस बात पर मतदान करने के लिए आमंत्रित किया कि क्या पंजाब को धर्म के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहिए। उन्होंने कैनडा स्थित हरदीप सिंह निज्जर के साथ भी मिलकर काम किया, जिनकी हत्या कैनडा और नई दिल्ली के बीच राजनयिक गतिरोध के केंद्र में रही है।

कैनडा में बढ़ रही खालिस्तानी गतिविधियों के पीछे गुरपतवंत सिंह पन्नू का हाथ है। यह वही पन्नू है , जो अक्सर सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बातें करता है। कैनडा मामले में भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत पन्नू ने एक वीडियो जारी कर भारतीय मूल के हिंदुओं को धमकी दी थी। इसके साथ ही, उनसे देश छोड़ने के लिए भी कहा था।

राज्य सरकार की अपील खारिज

जयपुर 23 सितंबर । राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में जल संसाधन विभाग से रिटायर हुए असिस्टेंट इंजीनियर के सेवा परिलाभ पर दिए ब्याज के मामले में राज्य सरकार की ओर से बिना कारण अपील दायर करने पर नाराजगी जताई है। और अदालत ने अपील को फिलूज बताते हुए राज्य सरकार पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया है। मुख्य न्यायाधीश ए.जी. मसीह व जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार बिना किसी उचित कारण ही अदालत में अपील दायर कर रही है।

अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले एएजी एसएस राघव को मौखिक तौर पर कहा कि सरकारी अफसरों की हर बात नहीं माननी चाहिए। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के अफसरों ने ही रिटायर हुए कर्मचारी के मामले की जांच में देरी की, जिससे उसे बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पाया।

- **वर्ष 2017 में वॉटर वर्क्स से रिटायर हुए एइएन को सेवा परिलाभ पर ब्याज के मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर अपील की हाई कोर्ट ने फिजूल बताया और 50,000 रू. का हर्जाना लगाया।**

वहीं एकलपीठ के आदेश के खिलाफ व्यर्थ की अपील पेश कर दी, जिससे अदालत में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ रही है।

मामले के अनुसार हरीश कुमार व्यास 30 जून, 2017 को जल संसाधन विभाग से रिटायर हुए थे। उसके खिलाफ किसी मामले में विभागीय जांच चल रही थी। इस जांच को पूरा करने में ही विभाग ने सात साल लगा दिए और यह 9 फरवरी 2021 को पूरी हुई। इसके चलते हरीश कुमार को सेवा परिलाभ के भुगतान में देरी हुई। उसने सेवा परिलाभ दिलवाने के लिए एकलपीठ में याचिका दायर की। जिस पर एकलपीठ ने 30 मार्च 2022 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को उपार्जित अवकाश की राशि देने का निर्देश देते हुए बकाया राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने का आदेश दिए। एकलपीठ के इस आदेश को राज्य सरकार ने बिना उचित कारण ही खंडपीठ में चुनौती दी।

राहुल छात्रा की स्कूटी पर बैठकर सभा स्थल पहुंचे

राहुल ने महारानी कॉलेज में मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की

जयपुर 23 सितंबर (का.प्र.)। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी शनिवार को प्रदेश के सबसे बड़े महिला महाविद्यालय, महारानी कॉलेज पहुंचे। पहले तो यहां उन्होंने मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की और फिर एक छात्रा के साथ स्कूटी पर बैठकर महारानी कॉलेज से मानसरोवर सभा स्थल के लिए रवाना हुए।

- **महारानी कॉलेज से राहुल गांधी हैलमेट लगाकर स्कूटी पर बैठकर मानसरोवर पहुंचे।**
- **राहुल ने महारानी कॉलेज में छात्राओं से बात की और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की।**

इससे पहले उन्होंने कॉलेज में छात्राओं से संवाद किया। राहुल ने यहां आने पर खुशी जताते हुए कहा कि, वो कई सारे शैक्षिणक संस्थानों में जा चुके हैं, लेकिन महारानी कॉलेज उन बैस्ट इन्स्टिट्यूट्स में से एक है, जहां वो गए हैं। आगे राहुल ने कहा कि, युवाओं के लिए जो जरूरी है, उस विषय पर बात होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर भी खुलकर अपने विचार रखे।

अन्य कार्यक्रमों से पहले महारानी कॉलेज पहुंचे राहुल गाँधी ने लाइब्रेरी विजिट की और फिर इसके बाद मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की। यहां से मानसरोवर स्थित सभा स्थल तक जब हैलमैट पहने राहुल गांधी एक छात्रा की स्कूटी पर बैठकर गए, उस समय उनकी सिक्यूरिटी के लोग मुख्य मार्ग टोंक रोड पर दौड़ते नज़र आए। राहुल गाँधी को अपनी स्कूटी पर पीछे बैठाने वाली छात्रा भी खासा उसाहित लग रह थी

मानसरोवर में सभा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सेंट्रल पार्क गए, जहां उन्होंने गांधी वाटिका का लोकार्पण किया।

प्र.मंत्री 9 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) की ओर से बताया गया है कि नई ट्रेन्स यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव देंगी और पर्यटन को बढ़ावा देंगी।

प्रधानमंत्री इन रूट्स की नई वंदे भारत एक्सप्रैस ट्रेन्स की शुरुआत करेंगे:-

1. उदयपुर-जयपुर
2. तिरुनेल्वेलि-मदुरै-चैन्नै
3. हैदराबाद-बैंगलुरु
4. विजयवाड़ा-चैन्नै (वाया रेनिगुन्टा)
5. पटना-हावड़ा
6. कसारागोड-तिरुवनन्तपुरम
7. राउरकेला-भुवनेश्वर-पुरी
8. रांचि-हावड़ा और
9. जामनगर-अहमदाबाद

पी.एम.ओ. की ओर से आगे बताया गया कि इन वंदे भारत ट्रेन्स से देश में रेल सेवाओं के एक नए सोपान की शुरुआत होगी।

इन ट्रेन्स में कवच तकनीकी सहित सुरक्षा के अत्याधुनिक साधन और विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। ये साधारणजनों, पेशेवरों, कारोबारियों, छात्र वर्ग और पर्यटकों को यात्रा का आधुनिक गतिशील एवं सहज साधन उपलब्ध करवाने की दिशा में एक कदम है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी में ए.बी.वी.पी. की जीत का परचम लहराया

ए.बी.वी.पी. ने अध्यक्ष समेत तीन पदों पर कब्जा किया, एन.एस.यू.आई. को एक सीट मिली

नई दिल्ली, 23 सितम्बर। दिल्ली विश्वविद्यालय में करोना महामारी की वजह से तीन साल बाद हुए छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ए.बी.वी.पी.) ने अध्यक्ष पद समेत तीन सीटों पर दर्ज की है जबकि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एन.एस.यू.आई.) ने उपाध्यक्ष पद पर जीत का परचम लहराया है। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर ए.बी.वी.पी. के तुषार डेढ़ा ने एन.एस.यू.आई. के हितेश गुलिया को 3,115 मतों से पराजित किया। अध्यक्ष पद पर ए.बी.वी.पी. के तुषार डेढ़ा को 23,460 मत मिले हैं जबकि अध्यक्ष पद पर एन.एस.यू.आई. हितेश गुलिया को 20,345 वोट मिले हैं।

वहीं उपाध्यक्ष पद पर एन.एस.यू.आई. के अभि दहिया को 22,331 वोट और ए.बी.वी.पी. सुशांत धनखड़ को 20,502 वोट मिले हैं। सचिव पद पर ए.बी.वी.पी. की अर्पिता को 24,534 वोट और वहीं एन.एस.यू.आई. की यक्षणा शर्मा को 11,597 वोट मिले हैं। सह सचिव पद पर ए.बी.वी.पी. के सचिन बैंसला को 24,955 वोट और एन.एस.यू.आई. के शुभम कुमार को 14,960 वोट मिले हैं।

- **दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में हर बार अच्छा प्रदर्शन करने वाले वामपंथी छात्रों के संगठन आइसा को इस बार एक भी सीट नहीं मिली।**
- **आइसा की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार को मात्र तीन हजार वोट ही हासिल हुये।**

डूसू चुनावों में शुक्रवार को 42 फीसदी वोट पड़े जो पिछले चुनाव (साल 2019) की तुलना में करीब 2.10 फीसदी अधिक थे। पिछले चुनाव यानी साल 2019 के चुनाव में 39.90 फीसदी वोट पड़े। तीन साल हुए इस चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में थे। डीयू के 52 कॉलेजों और केंद्रों पर वोट डाले गए थे।

कॉलेजों में बनाए गए पोलिंग स्टेशन पर तय समय पर सुबह 8.30 से वोटिंग शुरू हुई जो कि दोपहर एक बजे समाप्त हुई।

अब इंदिरा गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गिरिराज सिंह, जिन्होंने 1, सफदरजंग को सरकार को वापस किये जाने की मांग की है, ने इस तथ्य को अपने तर्क को आधार बनाया है-राष्ट्रीय राजधानी में इस समय सभी 15 पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिये एक स्मारक है।

सिंह ने एक्स पर कहा, "मैं मांग करता हूँ कि सारे भारत में बिखरे सभी राजवंशीय भवनों का आकलन किया जाये तथा इनकी तर्काधारित समीक्षा की जाये। इसका शुभारंभ करते हुये, 1, सफदरजंग कॉम्प्लैक्स को तुरंत भारत सरकार को वापस किया जाना चाहिये।

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार के कार्यकाल में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि भविष्य में कोई भी सरकारी बंगला राजनेताओं के स्मारक के रूप में तब्दील नहीं किया जायेगा। वर्ष 2014 में, नरेन्द्र मोदी सरकार ने भी इस नीतिगत निर्णय को दोहरा दिया था तथा इसके साथ ही, यह भी संकल्प लिया था कि, महात्मा गांधी के अलावा, किसी भी राजनेता की जयंती का जन्मदिन एवं पुण्यतिथि अब सरकार द्वारा नहीं मनाए जायेंगे।

- **वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था कि, महात्मा गांधी के अलावा किसी भी नेता की जयंती या पुण्यतिथि नहीं मनाई जायेगी।**

वर्ष 2018, बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में अपना 13 ए, माल एवेन्यू निवास खाली किया था जिसे उन्होंने बसपा के संस्थापक कांशीराम का स्मारक घोषित कर दिया था।

उन्होंने अपना आवास खाली करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश की अनुपालना में लिया था, जिसमें कहा गया था कि सभी पूर्व मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास खाली कर दें।

रूस, अमेरिका और चीन नई न्यूक्लियर वैपन परीक्षण साइट ढूंढ रहे हैं

नई दिल्ली, 23 सितम्बर। रूस, अमेरिका और चीन की न्यूक्लियर साइट को लेकर बड़ा दावा किया गया है। तीनों देशों ने अपने परमाणु साइट के पास नई फैसिलिटी तैयार की हैं। साथ ही हाल के वर्षों में नई सुरंगें भी खोदी गई हैं। सी.एन.एन. की ओर जारी सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से यह बात कही जा रही है। यह खबर ऐसे समय सामने आई है जब इन तीनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है और ये सभी बड़ी परमाणु शक्ति वाले देश हैं। क्या रूस, अमेरिका और चीन जल्द ही कोई न्यूक्लियर टैस्ट करने वाले हैं? जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें तो इसके सबूत नहीं मिलते हैं। एक्सपर्ट ने कहा, यह जरूर साबित होता है कि तीनों ही देशों की न्यूक्लियर साइट्स पहले की तुलना में बड़ी हो गई हैं।

बता दें कि चीन की न्यूक्लियर साइट शिनजियांग के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में है। रूस की यह साइट आर्कटिक महासागर द्वीपसमूह और अमेरिका की नेवादा रेगिस्तान में ऑपरेट होती है। सी.एन.एन. के अनुसार, जेफरी लुईस मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉनप्रोलिफरेशन स्टडीज के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा, न्यूक्लियर साइट के पास पहाड़ों के नीचे नई सुरंगों, सड़कों और स्टोरेज फैसिलिटी के साथ वाहनों के यातायात में वृद्धि हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह जानकारी सामने आई है। एक्सपर्ट ने कहा, ऐसे कई सारे हिंट मिल रहे हैं जो बताते हैं कि रूस, चीन और अमेरिका नए न्यूक्लियर टैस्ट फिर से शुरू कर सकते हैं। मालूम हो कि साल 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई थी। इसके तहत भूमिगत परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद से ही इन देशों ने ऐसा कोई टैस्ट नहीं किया है। चीन और अमेरिका ने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं, मगर उन्होंने इसका अनुमोदन नहीं किया। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक, दुनियाभर के 9 देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं।

- **विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि, ये तीनों देश जल्द न्यूक्लियर परीक्षण शुरु कर सकते हैं।**
- **गौरतलब है कि, साल 1996 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई थी। इसके तहत भूमिगत परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद से ही इन तीनों देशों ने कोई न्यूक्लियर वैपन टैस्ट नहीं किया है।**

वसंधुरा राजे ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा कि, मोदीजी ने महिला आरक्षण बिल के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि, मातृशक्ति की भागीदारी के बिना किसी भी राष्ट्र के नव निर्माण की कल्पना अधूरी है। यह बात उन्होंने अपने सरकारी आवास पर प्रदेश भर से आई महिलाओं से रक्षा सूत्र बंधावते हुए कही। उन्होंने कहा कि, यहाँ मौजूद महिलाओं का जोश देख कर यह तय है कि, नारी शक्ति का यह प्रवाह राजस्थान की महिला विरोधी कांग्रेस सरकार को बहा कर ले जाएगा।

राजे ने कहा, "रक्षासूत्र यूँ तो कच्चा धागा है, पर मज़बूत और अटूट है, मेरे लिए सुरक्षा कवच है। इसमें राजस्थान की संपूर्ण महिलाओं की शक्ति है जो मुझे हर मुश्किल को पार करने का हौसला देगा और प्रदेशवासियों की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।" पूर्व मु.मंत्री ने कहा कि, यह धागा उसे ही बांधें जो इस धागे का धर्म निभाये, जैसे भगवान कृष्ण। उन्होंने कहा कि, समाज रूपी बगीचा तब ही खूबसूरत दिखेगा जब उसमें सभी किस्मों के फूल समान भाव से खिलेंगे। अब मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाएं, जहां हमारी बेटियां बेखौफ़ अपना बचपन जी सकें। हमारी बहनें बिना किसी बाधा के अपने सपने पूरे कर सकें। हमारी माताएं सम्मान के साथ सिर ऊँचा करके चल सकें।

दिल्ली में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के निवासियों को उमस भरे मौसम में इस बारिश से राहत मिली। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार सुबह बताया कि "दिल्ली और एन.सी.आर. के सीमावर्ती क्षेत्रों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी तथा बिजली चमकने के साथ आंधी-तूफान और मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा था कि दिल्ली के ही हिण्डन एयर फोर्स स्टेशन, गाज़ियाबाद, इन्दिरापुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, सोनीपत और बल्लभगढ़ आदि एन.सी.आर. क्षेत्रों से तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है।

आरक्षण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विधेयक, जो जल्दबाजी में लाया गया, पारित तो हो गया लेकिन यह किसी को नहीं मालूम कि यह कानून लागू कब होगा। अगर सरकार के कुछ मंत्रियों तथा सांसदों के शब्दों पर यकीन किया जाये, तो यह कानून वर्ष 2039 तक लागू हो पायेगा।" सुप्रिया श्रीनाटे ने जानना चाहा कि इस आरक्षण विधेयक पारित करने के लिये संसद का विशेष सत्र बुलाने की सरकार को अचानक ही ऐसी क्या जल्दबाजी थी, जबकि इसे अधरझूल में छोड़ दिया जाना था। उन्होंने पूछा कि क्या यह अगले चुनावों में महिलाआं को प्रभावित करने का एक और साधन मात्र नहीं है।

प्रोटोकॉल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, विधायक और कई वी.आई.पी. भी पानी के लिए एक दूसरे को इशारा करते रहे, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई।

'नया संसद भवन भूलभुलैया जैसा है, दूसरे सांसदों के साथ संवाद ही नहीं हो पाता'

जयराम रमेश ने दावा किया कि, हॉल के कॉम्पैक्ट (सुगठित) नहीं होने की वजह से एक-दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता महसूस होती है

नई दिल्ली, 23 सितम्बर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि नए संसद भवन को "मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट" कहा जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उन्हें पुराने संसद भवन की याद आती है और उन्हें नया भवन "क्लॉस्ट्रोफोबिक" और "भूलभुलैया जैसा" लगता है। कांग्रेस ने संसद के नए भवन के डिजाइन को लेकर शनिवार को सवाल खड़े करते हुए दावा किया कि दोनों सदनों के बीच समन्वय खत्म हो गया है और इसमें घुटन महसूस होती है, जबकि पुराने भवन में खुलेपन का अहसास होता था। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद शायद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। नए संसद भवन में दोनों सदनों की कार्यवाही बीते विशेष सत्र में 19 सितंबर से शुरू हुई। पुराने भवन को अब 'संविधान सदन' के नाम से जाना जाता है।

रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "इतने भव्य प्रचार-प्रसार के साथ उद्घाटन किया गया नया संसद भवन प्रधानमंत्री के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। इसे 'मोदी मल्टीप्लेक्स' या 'मोदी मैरियट' कहा जाना चाहिए। चार दिन में मैंने देखा कि दोनों सदनों के अंदर और लॉबी में बातचीत एवं संवाद ख़त्म हो गया है।"

- **जयराम रमेश ने कहा कि, पुराने संसद भवन की कई विशेषताएं थीं। एक विशेषता यह भी थी कि, वहां बातचीत और संवाद की अच्छी सुविधा थी।**
- **जयराम रमेश ने कहा कि, नए संसद भवन को "मोदी मल्टीप्लैक्स या मोदी मैरियट" कहा जाना चाहिए।**

उन्होंने दावा किया, "हॉल के कंपैक्ट (सुगठित) नहीं होने की वजह से एक-दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता महसूस होती है। पुराने संसद भवन की कई विशेषताएं थीं। एक विशेषता यह भी थी कि वहां बातचीत और संवाद की अच्छी सुविधा थी। दोनों सदनों, सेंट्रल हॉल और गलियारों के बीच आना-जाना आसान था। नया भवन संसद के संचालन को सफ़ल बनाने के लिए आवश्यक जुड़ाव को कमज़ोर करता है। दोनों सदनों के बीच आसानी से होने वाला समन्वय अब अत्यधिक कठिन हो गया है।"

उनके मुताबिक, अगर आप पुरानी इमारत में खो जाते तो आपको अपना रास्ता फ़िर से मिल जाता क्योंकि वह गोलाकार है। नयी इमारत में यदि आप रास्ता भूल जाते हैं, तो भूलभुलैया में खो जाएंगे।

कांग्रेस महासचिव ने दावा किया, "पुरानी इमारत के अंदर और परिसर में खुलेपन का एहसास होता है, जबकि नई इमारत में घुटन महसूस होती है।" उन्होंने कहा, "अब संसद में भ्रमण का आनंद गायब हो गया है। मैं पुराने भवन में जाने के लिए उत्सुक रहता था। नया परिसर दर्दनाक और पीड़ा देने वाला है। मुझे यकीन है कि पार्टी लाइन से परे मेरे कई सहयोगी भी ऐसा ही महसूस करते होंगे।"

रमेश ने दावा किया, " मैंने सचिवालय के कर्मचारियों से यह भी सुना है कि नए भवन के डिज़ाइन में उन्हें काम में मदद करने के लिए आवश्यक विभिन्न व्यावहारिकताओं पर विचार नहीं किया गया है। ऐसा तब होता है जब भवन का उपयोग करने वाले लोगों के साथ ठीक से परामर्श नहीं किया जाता है।" उन्होंने कहा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद शायद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

'अगर अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक आतंकवादी था और एक वर्ष पूर्व एक प्रतिद्वंदी सिख नेता की हुई कथित हत्या में शामिल था।

वास्तव में ट्रूडो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह एक आतंकवादी को क्यों पनाह दिए हुए थी।

इस बीच, इसके बावजूद कि ट्रूडो ने "फाइव आईज़" सिक्योरिटी एग्रीमेन्ट ग्रुप के सदस्यों द्वारा भारत की तुरन्त एवं स्पष्ट निन्दा किये जाने का आव्हान किया है, इस प्रकार का कोई भी बयान सामने नहीं आया। जहाँ अमेरिका ने इस पर किसी प्रकार की अधिकृत टिप्पणी नहीं की है, कैनडा में अमेरिका के राजदूत ने कहा कि कुछ खुफिया शेयरिंग हुई है।

पूरा विवाद एवं दावे तथा कत्ल के दावे पूरे दोषारोपण के पीछे के कारणों के कई स्तरों की ओर संकेत कर रहे हैं। बताया जाता है कि जस्टिन ट्रूडो राजनैतिक दबाव में है तथा इससे उसके द्वारा एकाएक किये गये रहस्योदघाटनों का आंशिक स्पष्टीकरण भी मिलता है। इसके परिणामस्वरूप वे हार्ड फैक्ट्स को लेकर आगे नहीं आ रहे हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908